सच कहने की ताकत

साप्ताहिक समाचार पत्र

जालंधर ब्रीज

प्रेरणा

"सकारात्मक सोच ही जीवन की सबसे बड़ी ताकत है।"

साप्ताहिक मौसम

दिन	अधिकतम	न्यूनतम
शुक्रवार	24°	6°
शनिवार	25 °	7°
रविवार	19°	7°
सोमवार	18°	7°
मंगलवार	19°	7°
बुधवार	18°	8°
वीरवार	20°	6°

*आंकड़े आईएमडी के अनुसार

www.jalandharbreeze.com • JALANDHAR BREEZE • WEEKLY • YEAR-7 • 05 DECEMBER TO 11 DECEMBER 2025 • VOLUME 20 • PAGE-4 • RATE-3.00/- • RNI NO.: PUNHIN/2019/77863

Lic No : 933/ALC-4/LA/FN:1184
INNOVATIVE TECHNO INSTITUTE
CONSULTING DESIGN TRAINING
INNOVATIVE TECHNO INSTITUTE
ISO CERTIFIED 2015 COMPANY

CONFUSED ABOUT CAREER!
Unsure of what to do after 10th/12th/Graduation?
Whether to Study in India or Abroad?

What should I do after 10th-Science, Commerce or Arts?
Should I consider Computer or Mechanical Engineering?
What is better for me - MBA in Marketing or MBA in Finance?
Should I pursue Chartered Accountancy or Law after 12th?
Do I have the aptitude for Architecture and Designing?
Get Career Guidance from our Expert Career Counseling Team Free of Cost

E-mail : hr@innovativetechin.com • Website : www.innovativetechin.com • FB/Innovativetechin • Contact :9317776662, 9317776663
REGIONAL OFFICE : S.C.O No. 10 Gopal Nagar, Near Batra Palace, Jal. HEAD OFFICE : S.C.O No. 21-22, Kuldip Lal Complex, Highway Plaza GT Road, Adjoining Lovely Professional University. Phagwara.
*T&C apply

भारत पहुंचे पुतिन से गले मिले मोदी, एक ही गाड़ी में बैठकर पहुंचे पीएम आवास

नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दिल्ली के पालम टेक्निकल एयरपोर्ट से एक ही कार में रवाना हुए। पुतिन भारत की दो दिवसीय राजकीय यात्रा पर हैं। वह 5 दिसंबर को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 23वें भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। भारत और रूस के बीच मजबूत संबंधों को रेखांकित करने वाले एक दुर्लभ कूटनीतिक कदम के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को मानक प्रोटोकॉल तोड़ते हुए दिल्ली एयरपोर्ट पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का स्वागत किया।

क्रेमलिन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विमान रैंप पर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का स्वागत करने का कदम अप्रत्याशित था और रूसी पक्ष को इसकी जानकारी पहले से नहीं दी गई थी। नरेन्द्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पालम हवाई अड्डे से रवाना होने के कुछ ही मिनट बाद दिल्ली में 7,

लोक कल्याण मार्ग स्थित प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास पर पहुंचे। प्रधानमंत्री आवास पर डिनर का आयोजन किया गया जिसमें राष्ट्रपति पुतिन-पीएम मोदी शामिल हुए। यह कदम दोनों नेताओं के बीच रणनीतिक साझेदारी और घनिष्ठ संबंधों को दर्शाता है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन गुरुवार को दो दिवसीय राजकीय यात्रा पर भारत पहुंचे हैं। यह भाव उस समय एक गर्मजोशी भरा स्मरण था जब दोनों नेता 1 सितंबर को चीन के तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन में रूसी राष्ट्रपति के ऑरस सीनेट में द्विपक्षीय बैठक स्थल तक कार से गए थे। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ यात्रा पर आने के लिए लगभग 10 मिनट तक प्रतीक्षा की।

भारत पहुँचने पर पुतिन का औपचारिक स्वागत किया गया जिसने भारत और रूस के बीच मज़बूत संबंधों को उजागर किया। पुतिन की भारत यात्रा पश्चिमी अलगाव के बावजूद वैश्विक प्रभाव बनाए रखने के रूस के प्रयासों को उजागर करती है। यह यात्रा वैश्विक राजनीति में भारत के रणनीतिक संतुलन को रेखांकित करती है, जो पश्चिम के साथ संबंधों को संतुलित करते हुए रूस के साथ संबंधों को मज़बूत करेगी।

प्रमुख चर्चाओं में यूक्रेन संघर्ष, अफ़ग़ानिस्तान और भारत-रूस रणनीतिक साझेदारी का विस्तार शामिल हो सकता है। 2022 में मास्को द्वारा यूक्रेन पर पूर्ण आक्रमण शुरू करने के बाद 2021 के बाद पुतिन की यह पहली भारत यात्रा होगी। इस यात्रा में व्यापार, रक्षा सहयोग और ऊर्जा साझेदारी को बढ़ावा देने पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस यात्रा के दौरान दिल्ली और मास्को के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। यह यात्रा अमेरिका द्वारा भारत पर रूसी तेल खरीदना बंद करने के लिए दबाव बढ़ाने के कुछ महीनों बाद हो रही है।

कथित वायरल ऑडियो पर याचिका दायर, अदालत ने मेंटेनेबिलिटी पर मांगा स्पष्टीकरण

चंडीगढ़ (जालंधर ब्रीज). जिला पटियाला में हो रही ज़िला परिषद और पंचायत समिति चुनावों से संबंधित पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में दायर एक जनहित पटीशन का पंजाब सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल मनिंदरजीत सिंह बेदी ने कड़ा विरोध किया है। यह पटीशन एक कथित कॉन्फ्रेंस कॉल की उस ऑडियो रिकॉर्डिंग पर आधारित है, जो वायरल हुई थी। राज्य सरकार ने संवैधानिक अदालतों में इस पटीशन के गैर-वाज़िब होने संबंधी मूलभूत एतराज उठाये हैं। एडवोकेट जनरल ने सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न मामलों में दिए गए निर्णयों का हवाला देते हुए दलील दी कि चुनावों से संबंधित मामलों में ऐसी अपीलें मेंटेनेबल नहीं होतीं।

अमेरिका ने 2009 से अब तक 18,822 भारतीयों को भेजा भारत : जयशंकर

विदेश मंत्री ने राज्यसभा में दी जानकारी

नई दिल्ली. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को राज्यसभा में कहा कि अमेरिका ने वर्ष 2009 से अब तक कुल 18,822 भारतीय नागरिकों को निर्वासित किया है, जिनमें जनवरी 2025 से अब तक निर्वासित किए गए 3,258 भारतीय शामिल हैं। उच्च सदन में पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए जयशंकर ने कहा कि मानव तस्करी के मामलों की जांच राज्यों के साथ-साथ राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने भी की है, जिनमें पंजाब में सर्वाधिक मामले दर्ज हुए हैं। उन्होंने एक लिखित उत्तर में बताया कि 2009 से अब तक कुल 18,822 भारतीय नागरिकों को भारत वापस भेजा गया है। मंत्री ने बताया कि वर्ष 2023 में 617 भारतीयों को और 2024 में 1,368 भारतीयों को अमेरिका से निर्वासित किया गया। उन्होंने कहा कि जनवरी 2025 से अब तक कुल 3,258 भारतीय नागरिकों को अमेरिका ने भारत निर्वासित किया है। इनमें से 2,032 भारतीय (लगभग 62.3 प्रतिशत) नियमित वाणिज्यिक उड़ानों से और शेष 1,226 भारतीय (37.6 प्रतिशत) अमेरिकी आव्रजन एवं सीमा शुल्क प्रवर्तन (आईसीई) या सीमा शुल्क एवं सीमा सुरक्षा(सीबीपी) द्वारा संचालित चार्टर उड़ानों से लौटे हैं।

पंजाब में मानव तस्करी के सर्वाधिक मामले

विदेश मंत्री ने कहा कि राज्यों में पंजाब में मानव तस्करी के सर्वाधिक मामले हैं। 'पंजाब सरकार ने एसआईटी और तथ्य-अन्वेषण समिति गठित की है। उनकी ओर से मिली जानकारी के अनुसार, 58 अवैध ट्रैवल एजेंटों के खिलाफ 25 प्राथमिकी दर्ज हुई हैं और 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।''

एक साल के अंदर नया टोल कलेक्शन सिस्टम होगा लागू

गडकरी ने लोकसभा में दिया जवाब

नई दिल्ली. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को कहा कि टोल कलेक्शन का मौजूदा सिस्टम एक साल के अंदर खत्म हो जाएगा और इसकी जगह एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ले लेगा जिससे हाईवे पर गाड़ी चलाने वालों को बिना रुकावट के चलने का अनुभव मिलेगा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान कहा कि नया सिस्टम 10 जगहों पर शुरू किया गया है और एक साल के अंदर इसे पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह टोल सिस्टम खत्म हो जाएगा। टोल के नाम पर आपको कोई नहीं रोकेगा। एक साल के अंदर पूरे देश में इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन लागू कर दिया जाएगा।

देश में चल रहे 4,500 हाईवे प्रोजेक्ट : गडकरी ने सदन को यह भी बताया कि अभी देश भर में 10 लाख करोड़ रुपये के 4,500 हाईवे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। हाल ही में जारी एक ऑफिशियल बयान के अनुसार, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) ने नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन (एनईटीसी) प्रोग्राम बनाया है, जो इलेक्ट्रॉनिक टोल पेमेंट के लिए एक यूनिफाइड, इंटरऑपरेबल प्लेटफॉर्म है, ताकि भारत के हाईवे पर टोल कलेक्शन को आसान बनाया जा सके।

बिक्रम मजीठिया की मुश्किलें बढ़ीं, हाईकोर्ट ने जमानत देने से किया इंकार

चंडीगढ़. पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने गुरुवार को कथित धन शोधन मामले में शिरोमणि अकाली दल (शिअद) नेता बिक्रमजीत सिंह मजीठिया की ज़मानत याचिका खारिज कर दी। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के एडिशनल एडवोकेट जनरल फेरी सोफत ने कहा कि मजीठिया को अवैध धन हस्तांतरण के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था और इन्हीं लेन-देन के आधार पर अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी। मजीठिया ने लंबी हिरासत का हवाला देते हुए मामले में ज़मानत की मांग करते हुए राजनीतिक प्रतिशोध का आरोप लगाया था। वकील फेरी सोफत ने बताया कि विभिन्न कंपनियों के माध्यम से अवैध धन हस्तांतरण की एसआईटी रिपोर्ट के आधार पर उन्हें 25 जून को गिरफ्तार किया गया था। मजीठिया की दलील थी कि कार्यवाही और हिरासत को लंबा खींच दिया गया है, और यह सब एक राजनीतिक प्रतिशोध है। अदालत ने मामले की गंभीरता को समझते हुए आज उनकी याचिका खारिज कर दी। मनी लॉन्ड्रिंग के लेन-देन में कई फर्जी कंपनियां शामिल थीं। इन कंपनियों में साइप्रस से धन हस्तांतरित किया गया था और इन सभी तर्कों के आधार पर, अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी।

धमकियां और प्रचार काम नहीं आए, अदालत ने सच देखा : पन्नू

चंडीगढ़ (जालंधर ब्रीज). आम आदमी पार्टी (आप) पंजाब के महासचिव और मीडिया इंचार्ज बलतेज पन्नू ने कहा कि गुरुवार को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के फैसले ने अकाली दल (बादल) को सबसे बड़ा झटका दिया है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को बार-बार दी गई उनकी धमकियां काम नहीं आईं। चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पन्नू ने कहा कि अदालत ने वरिष्ठ अकाली नेता और पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है, जिससे उनके खिलाफ दर्ज विजिलेंस केस की गंभीरता की पुष्टि होती है। पन्नू ने कहा कि इससे पहले निचली अदालत मजीठिया की जमानत पहले ही खारिज कर चुकी थी।

सोनिया गांधी का केंद्र पर हमला वायु प्रदूषण पर तत्काल रोक लगाएं

नई दिल्ली. कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने गुरुवार को केंद्र से दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए कदम उठाने की मांग की और कहा कि बच्चे और बुजुर्ग इससे जूझ रहे हैं। संसद के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि कुछ करना सरकार की ज़िम्मेदारी है। छोटे बच्चे तो परेशान हैं ही, मेरे जैसे बुजुर्गों के लिए भी यह मुश्किल है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी इस मुद्दे को उठाया और आरोप लगाया कि कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि विपक्ष इस मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं करना चाहता और जब प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए कदम उठाए जाएँगे तो वह केंद्र के साथ खड़ा रहेगा। कांग्रेस सांसद ने कहा कि हमें किस मौसम का आनंद लेना चाहिए? बाहर की स्थिति देखिए। जैसा कि सोनिया जी ने कहा, बच्चे साँस नहीं ले पा रहे हैं। उन्हें अस्थमा है और उनके जैसे वरिष्ठ नागरिकों को साँस लेने में कठिनाई हो रही है। स्थिति साल-दर-साल बदतर होती जा रही है। हर साल सिर्फ़ बयानबाज़ी होती है, कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती।

सभी ने कहा है कि सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए और हम सभी उनके साथ खड़े हैं। यह कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं कि हम एक-दूसरे पर उंगली उठाएँ।

इससे पहले आज, विपक्षी सांसदों ने दिल्ली-एनसीआर और उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में वायु प्रदूषण को लेकर केंद्र के ख़िलाफ़ संसद परिसर में मकर द्वार के सामने विरोध प्रदर्शन किया। सांसदों को ऑक्सीजन मास्क पहने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करते हुए एक बैनर पकड़े देखा गया, जिस पर लिखा था, "मौसम का मज़ा लीजिए"। बैनर पर यह टिप्पणी संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत में प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन के बाद आई है, जिसमें उन्होंने यह बात कही थी।

अकाली दल गुंडागर्दी या गैर-कानूनी दखलअंदाज़ी बर्दाश्त नहीं करेगा : झिंजर

• **जालंधर ब्रीज.** घनौर

हल्का घनौर इंचार्ज सरबजीत सिंह झिंजर ने प्रेस को बताया कि आम आदमी पार्टी ने शिरोमणि अकाली दल के उम्मीदवारों को नामांकन पत्र भरने से रोकने के लिए हर संभव कोशिश की। लेकिन इन सभी हथकंडों के बावजूद, अकाली उम्मीदवारों ने घनौर के 16 में से 15 ज़ोन और शंभू क्षेत्र के 19 में से 14 ज़ोन में सफलतापूर्वक अपने नामांकन पत्र दाखिल कर दिए। उन्होंने कहा कि गांवों में अकाली दल के पक्ष में बढ़ती लहर को देखते हुए आम आदमी पार्टी की सरकार बेहद घबराई हुई है और इसी घबराहट में सरकार अपने कार्यकर्ताओं और उम्मीदवारों से धक्केशाही करवा रही है। सरबजीत सिंह झिंजर ने बताया कि नामांकन प्रक्रिया के दौरान 'आप' कार्यकर्ताओं ने सरकारी शह के साथ अकाली दल उम्मीदवारों के नामांकन पत्र छीनकर फाड़ दिए और पुलिस ने अकाली कार्यकर्ताओं से धक्कामुक्की भी की। यह सब सरकार के दबाव में हुआ है जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सीधा उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि अगर आम आदमी पार्टी ने पिछले समय में कोई अच्छा काम किया होता, तो आज उन्हें निष्पक्ष चुनावों से डर नहीं लगता।

झिंजर ने पूरा भरोसा जताया कि हाल ही में लीक हुई एसएसपी और अधिकारियों की ऑडियो रिकॉर्डिंग का ज़िक्र करते हुए झिंजर ने कहा कि इस रिकॉर्डिंग ने साबित कर दिया है कि पुलिस प्रशासन, आम आदमी पार्टी के साथ मिलीभगत कर चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। यह रिकॉर्डिंग लोकतंत्र के साथ हो रही सबसे बड़ी धोखाधड़ी की गवाही है। उन्होंने मांग की कि चुनाव को निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए पोलिंग से पहले और पोलिंग के दिन केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती बेहद ज़रूरी है।

नारी शक्ति से विकास: महिलाओं के नेतृत्व वाली प्रगति पर फोकस करने

• **जालंधर ब्रीज.** नई दिल्ली

लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण हमारे उज्जवल आज और बदलते कल के लिए बेहद ज़रूरी आधार है। तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ते इस वक्त में हम लैंगिक समानता हासिल करने के लिए एक और शताब्दी तक इंतज़ार नहीं कर सकते। नारी शक्ति और भारत की विश्व को सभ्यतागत देन, महिलाओं को देवी के रूप में देखने की मूल अवधारणा को अब महज़ एक प्रतीक से आगे ले जाकर व्यावहारिक जीवन में लाना होगा और महिलाओं के प्रति सम्मान की हमारी विरासत को महिलाओं के नेतृत्व वाले सतत् विकास के मार्ग पर ले जाना होगा। जब आधी मानवता की स्वतंत्रता और जीवन जीने के अवसर बढ़ते हैं, तो नए समाज में फिर से एक नई ऊर्जा का संचार होता है। लैंगिक समानता अपने आप में एक आदर्श विचार है, और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, तकनीकी और पर्यावरणीय प्रगति का एक शक्तिशाली कारक भी है। मैकिन्से ग्लोबल इंस्टीट्यूट की 2015 की रिपोर्ट, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों पर आधारित वर्ष 2024 का विश्लेषण और ईवाय का इंडिया@100 कार्य, मिलकर एक ठोस आर्थिक तर्क पेश करते हैं: लैंगिक अंतर को कम करने से सकल घरेलू उत्पाद में 20 से 30% की वृद्धि हो सकती है और यह भारत के लिए 2047 तक 28 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लिए बेहद ज़रूरी है।

भारत एक जनसांख्यिकीय दौर से गुज़र रहा है। हमारी युवा आबादी का तभी लाभ उठाया जा सकता है, जब वह महिलाओं के लिए फायदेमंद हो। प्रजनन क्षमता घट रही है और लड़कियों तथा युवतियों की महत्वाकांक्षाएँ बढ़ रही हैं, भारत अब उच्च शिक्षा में लगभग बराबरी पर है और करीब 43% स्टेम छात्राएँ हैं। कई सालों तक महिलाओं के काम को अनौपचारिक और अदृश्य बनाए रखने के बाद, आखिरकार महिलाओं की श्रमशक्ति में भागीदारी फिर से बढ़ने लगी है और अब इसे बेहतर गुणवत्ता, औपचारिक और भविष्य के लिए तैयार नौकरियों में तब्दील होना चाहिए।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की एक खास विशेषता ऐसे प्रमुख कार्यक्रमों को लक्षित करना है, जिनमें महिलाएँ प्रमुख लाभार्थी हैं। इसके अलावा बुनियादी ढाँचे, स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े ऐसे कार्यक्रम भी सरकार के फोकस में हैं, जो लैंगिक भेदभाव के प्रति संवेदनशील हैं। छात्रवृत्ति, छात्रावास और आरक्षित सीटों ने उच्च एवं तकनीकी शिक्षा में महिलाओं की मौजूदगी को बढ़ाया है और ज्ञान, स्वास्थ्य, हरित और देखभाल अर्थव्यवस्थाओं में उनके लिए नए रास्ते खोले हैं। डिजिटल मिशन और ग्रामीण कार्यक्रमों ने करोड़ों महिलाओं को प्रशिक्षित किया है और उनके हाथों में किफायती डेटा वाले स्मार्टफोन और जन धन खाते दिए हैं, जिससे उन्हें सूचना, बाज़ार और सेवाओं तक सीधी पहुँच मिली है।

लक्ष्मी पुरी
(संयुक्त राष्ट्र की पूर्व सहायक महासचिव और लैंगिक समानता तथा महिला-नेतृत्व वाले विकास की एक अग्रणी वैश्विक समर्थक हैं।)

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा, स्वच्छ भारत और प्रधानमंत्री आवास जैसी प्रमुख योजनाओं ने करोड़ों महिलाओं को स्वच्छ ऊर्जा, ऋण तक पहुँच, स्वच्छता और सुरक्षित आवास जैसी सुविधाएं दी हैं, जबकि सुकन्या समृद्धि और लखपति दीदी जैसी योजनाओं ने उनके बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण और उनकी आय में बढ़ोत्तरी को मुमकिन बनाया है। अब अगले स्तर पर उन्हें निर्णायक रूप से लाभार्थी से अधिकार पति, यानी अधिकारों के प्राप्तकर्ता से पूर्ण अधिकार धारक और अर्थव्यवस्था तथा समाज में फैसला लेने वाली महिला के रूप में स्थापित करना होगा। 2030 तक लैंगिक समानता पर सतत् विकास लक्ष्य 5 को प्राप्त करने का यही असल सार है।

भारत में अंतर्संबंध का अर्थ है, कि कई महिलाओं को गरीबी, जाति, जनजाति, धर्म, दिव्यांगता या स्थान के कारण कई स्तरों पर मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तीन तलाक के उन्मूलन ने मुस्लिम महिलाओं के विवाह अधिकारों को मज़बूत किया है। जनजातीय पृष्ठभूमि की महिला, द्रौपदी मुर्मू का भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव इस बात का प्रतीक है कि हाशिए पर रहने वाले समाज की महिला एक गणतंत्र में किस ऊँचाई तक पहुँच सकती है और लैंगिक और सामाजिक न्याय के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को और गहरा कर सकती है। मौजूदा वक्त में हमें जिस कल का निर्माण करना है, वह ऐसा होना चाहिए, जिसमें विकास के ऐसे उदाहरण, असाधारण न होकर, व्यवस्था का हिस्सा हों और व्यापक रुप से दिखाई दें।

हिंसा से मुक्ति, एक लैंगिक समानता वाले समाज का अनिवार्य आधार बनी हुई है। घरेलू दुर्व्यवहार और मानव तस्करी से लेकर कार्यस्थल पर उत्पीड़न और ऑनलाइन घृणा तक, महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हर प्रकार की हिंसा को खत्म करना, हमारे एजेंडे में सबसे ऊपर होना चाहिए, साथ ही महिलाओं के स्वास्थ्य और यौन तथा प्रजनन अधिकारों पर निरंतर काम करना चाहिए, जो स्वायत्तता और सम्मान की गारंटी देते हैं।

राजनीतिक आवाज़ और नेतृत्व हर दूसरे हस्तक्षेप के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देते हैं और महिलाओं को भविष्य के नियमों को आकार देने की ताकत देते हैं। जमीनी स्तर पर, पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों में 33% से 50% आरक्षण ने 15 लाख महिला नेताओं को जन्म दिया है। लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं में एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने वाला नारी शक्ति वंदन अधिनियम, कानून निर्माण और शासन में वास्तविक समानता की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। जैसा कि हाल ही में बिहार में देखा गया, महिलाएँ चुनावी नतीजों को भी नया रूप दे रही हैं, जहाँ जागरूक मतदाता सुरक्षा, गतिशीलता, शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका के क्षेत्र में काम करने वाली सरकारों को चुन रहे हैं।

घूमने का प्लान बना रहे हैं? मध्य प्रदेश की ये जगहें बिल्कुल मिस ना करें

Travelling मध्य प्रदेश भारत का सांस्कृतिक और प्राकृतिक हृदय है जहां ऐतिहासिक धरोहरें, घने जंगल, खूबसूरत झीलें और प्राचीन मंदिर मिलकर इसे एक परफेक्ट ट्रैवल डेस्टिनेशन बनाते हैं। यह हर तरह के यात्रियों को अनोखा अनुभव देता है।

• **जालंधर ब्रीज .** फीचर

मध्य प्रदेश जिसे भारत का हृदय कहा जाता है, देश के सबसे विविधतापूर्ण पर्यटन स्थलों में से एक है। यहां इतिहास, प्रकृति, संस्कृति और रोमांच- सभी का अद्भुत संगम मिलता है। इस राज्य की विशाल धरोहरों में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, विश्वप्रसिद्ध टाइगर रिजर्व, प्राचीन मंदिर, झीलें और खूबसूरत पहाड़ियां शामिल हैं जो इसे यात्रियों के लिए आकर्षण का केंद्र बनाती हैं। मध्य प्रदेश जाएं तो इन जगहों पर जरूर घूमकर आएं।

खजुराहो : सबसे पहले बात करते हैं खजुराहो की, जो अपनी अनोखी शिल्पकला वाले मंदिरों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यहां की सुंदर नक्काशी और वास्तुकला भारतीय सांस्कृतिक इतिहास का अनमोल उदाहरण है।

भोपाल : इसके बाद भोपाल आता है, जिसे झीलों का शहर कहा जाता है। यहां बड़ा तालाब, भीमबेटका गुफाएं और भारत भवन जैसे स्थल इतिहास और आधुनिकता का संतुलन दिखाते हैं।

पचमढ़ी : प्रकृति प्रेमियों के लिए पचमढ़ी एक स्वर्ग जैसा हिल स्टेशन है। यह घने जंगलों, झरनों और शांत घाटियों के कारण मध्य भारत का सबसे सुंदर हिल स्टेशन माना जाता है।

इंदौर : स्वच्छता के लिए लगातार चर्चित इंदौर को मध्य भारत का खाद्य स्वर्ग कहा जाता है। यहां सराफा नाइट स्ट्रीट, राजवाड़ा, लालबाग पैलेस, 56 दुकान, आदि का आनंद ले सकते हैं।

टाइगर रिजर्व : रोमांच पसंद यात्रियों के लिए कान्हा और बांधवगढ़ के टाइगर रिजर्व प्रमुख आकर्षण हैं जहां सफारी का अनोखा अनुभव और बाघों को देखने का मौका मिलता है।

महाकालेश्वर-ओंकारेश्वर : धार्मिक यात्रा के इच्छुक लोगों के लिए उज्जैन एक महत्वपूर्ण स्थान है, जहां महाकालेश्वर मंदिर दुनिया भर के भक्तों को आकर्षित करता है। इसके साथ ही ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के भी दर्शन करके आ सकते हैं।

ओरछा : ओरछा शांत सुंदरता, नदी किनारे स्थित प्राचीन महलों और मंदिरों के लिए जाना जाता है।

सांची स्तूप : यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, सांची स्तूप इतिहास और बौद्ध कला प्रेमियों के लिए किसी खजाने से कम नहीं है।

LIFESTYLE

लाइफस्टाइल डॉक्टर ने बताईं 7 स्किल्स जो हर महिला को सीखनी चाहिए, चेक करें क्या आप हैं सही ट्रैक पर?

अगर आप महिला हैं या आपके आसपास कोई ऐसी महिला है जो हमेशा दूसरों की फिक्र करती है और अपना असतित्व भूलती जा रही है तो लाइफस्टाइल डॉक्टर की सुझाई 7 स्किल्स उन्हें सीखनी चाहिए।

• **जालंधर ब्रीज .** फीचर

महिलाएं सुबह से उठकर रात तक दूसरों के लिए कुछ ना कुछ करती रहती हैं। ऐसे में फ्रस्ट्रेटेड होना और चिड़चिड़ा होना स्वाभाविक है। कुछ काम ऐसे भी हैं जो जरूरी लाइफ स्किल्स हैं, महिलाओं को जरूर आनी चाहिए। लाइफस्टाइल एक्सपर्ट ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में ऐसी 7 स्किल्स बताई हैं जो महिलाओं को जरूर आनी चाहिए।

एक्सपर्ट ने बताया कि उन्होंने यह वीडियो इसलिए बनाया है कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं के काम आ सके। एक्सपर्ट ने बताया कि पुरुषों को भी स्किल्स सीखनी चाहिए लेकिन महिलाओं को पहले सीखनी चाहिए।

फाइनैंसेज और ई-बैंकिंग

महिलाओं का अपना बैंक अकाउंट और इसमें पैसा होना बहुत जरूरी है। अगर वे काम करतीं, पैसे कमाती हैं या काम करना चाहती हैं तो और भी ज्यादा। उन्हें फोन बैंकिंग भी आनी चाहिए साथ ही फ्रॉड्स से बचना भी।

ना कहना

ना कहने से आपके मन में काफी शांति रहती है। आपके लिए समय भी रहता है और अच्छा लगता है। शुरू में थोड़ा अजीब लग सकता है। इसीलिए ना कहना है सीखना एक जरूरी स्किल है।

खुद को प्राथमिकता देना

आप दूसरों के लिए लगे रहते हैं लेकिन खुद के लिए पहले करना चाहिए। जैसे एयर होस्टेस बोलती हैं, पहले अपना मास्क लगाएं फिर दूसरों की मदद करें। अगर खुद को हां कहना सीखेंगे तो जीवन में आप अपने लिए भी ऐसा ही करेंगे। एक्सरसाइज करना एक ऐसा ही तरीका है जिसमें आप खुद को हां कहते हैं।

सेल्फ डिफेंस सीखना

एक्सपर्ट बताते हैं, मैं मानता हूं, ये गलत है कि आपको सेल्फ डिफेंस सीखने की जरूरत है लेकिन आज कोई और रास्ता भी नहीं है। इसलिए आप थोड़ा-बहुत जरूर सीखें चाहे वर्कआउट के फॉर्म में ही।

खुद को एक्प्रेस करें

अपने मन की बात जाहिर करें। इसलिए नहीं कि आप सफाई देना चाहती हैं बल्कि इससे आपके लिए भी क्लैरिटी बनेगी। इससे आप बेहतर बनेंगी, स्ट्रेस भी अच्छी तरह हैंडल कर पाएंगी।

ड्राइविंग सीखें

ड्राइविंग सीखना आपको इंडिपेंडेंट और कॉन्फिडेंट बनाएगा। क्राइसिस के मौके पर कोई ना होने पर आपके लिए यह काफी मददगार साबित हो सकता है।

रिलैक्स करें

आराम करने के लिए 10 मिनट ही सही पर वक्त निकालें। आराम करें, कुछ ना करें, किताब पढ़ें, कोई हॉबी चुनें यह हर महिला के लिए जरूरी है। सुबह उठने से लेकर सोने तक भागमभाग से आप उलझी रहती हैं। यह चीज आपको फ्रस्ट्रेट करती और चिड़चिड़ा बनाती है। बिना किसी अपराधबोध के अपने लिए वक्त निकालें।

डिस्क्लेमर : इस लेख के सुझाव सामान्य जानकारी के लिए हैं। इन सुझावों और जानकारी को किसी डॉक्टर या मेडिकल प्रोफेशनल की सलाह के तौर पर न लें। किसी भी बीमारी के लक्षणों की स्थिति में डॉक्टर की सलाह जरूर लें।

सर्दियों में ठंड से बचना है तो बच्चों-बड़ों सबको बनाकर खिलाएं बाजरे के लड्डू

सर्दियों में घरवालों को हेल्दी रखना चाहती हैं। जिससे वो ठंड से बचे रहें तो उन्हें बाजरे के आटे से बने ये लड्डू बनाकर खिलाएं। इन लड्डुओं को बनाना बिल्कुल आसान हैं और ये कम मेहनत में ही बनकर रेडी हो जाते हैं।

• **जालंधर ब्रीज.** रेसिपी

सर्दियों के मौसम में खानपान में ऐसी चीजों को शामिल करना चाहिए। जो शरीर को अंदर से गर्म रखने में मदद करें। जिससे कि बाहरी ठंडक का असर शरीर के मेटाबॉलिज्म, डाइजेशन पर ना पड़े और शरीर अंदर से गर्म बना रहे।

सर्दियों में तिल, गुड़, मेवा और मिलेट जैसे बाजरा खाने की सलाह मिलती है। तो अगर आप घरवालों को हेल्दी रखना चाहती हैं तो बाजरे से बने इन लड्डुओं को जरूर खिलाएं। नोट कर लें बिल्कुल आसान सी रेसिपी।

बाजरे के लड्डू बनाने की सामग्री

- ✓ बाजरे का आटा दो सौ ग्राम
- ✓ गुड़ 250 ग्राम
- ✓ घी 150 ग्राम
- ✓ काजू 10-12
- ✓ बादाम 10-12
- ✓ गोंद 2 टेबल स्पून
- ✓ दो से तीन चम्मच नारियल का बूरा
- ✓ इलायची पाउडर आधा छोटा चम्मच

बाजरे का लड्डू बनाने की रेसिपी

- ✓ सबसे पहले कड़ाही में घी गर्म करें और बाजरे के आटे को घी में डालकर धीमी आंच पर भूनें। एक बार आटा भुन जाए तो प्लेट में निकाल लें।
- ✓ अब उसी कड़ाही में घी डालें और गोंद को फूलने तक भूनकर निकाल लें।
- ✓ कड़ाही को गर्म कर उसमे नारियल के बुरादे को हल्का सा रोस्ट कर लें। ध्यान रहे कि ये सुनहरा ना होने पाएं।
- ✓ बाजरे का आटा और गोंद भुनने के बाद गुड़ को कड़ाही में डालें और धीमी आंच पर पिघलने दें। गुड़ के पिघलते ही गैस की फ्लेम को बंद कर दें और इसमे बारीक कटे बादाम, काजू, पिस्ता और मनचाहे ड्राई फ्रूट्स एंड नट्स को मिला लें।
- ✓ बाजरे का आटा, नारियल का बुरादा गुड़ में डालें और मिक्स करें।
- ✓ साथ ही इलायची पाउडर स्वाद और महक के लिए डाल दें।
- ✓ अच्छी तरह से मिक्स करें और लड्डू का मिक्सचर तैयार है।
- ✓ पिघला घी साथ में रखें और हथेलियों पर हल्का सा लगाकर लड्डू के मिक्सचर को मुट्ठी में भरकर बांधें।
- ✓ इसी तरह से सारे लड्डूओं को हाथों पर देसी घी लगाकर तेजी से बांधते जाएं।
- ✓ बस तैयार हैं सर्दियों में फायदा पहुंचाने वाले बाजरे के लड्डू।

सर्दियों में सुबह नहीं खुलती बच्चों की आंख, आलस दूर भगाएंगे ये टिप्स

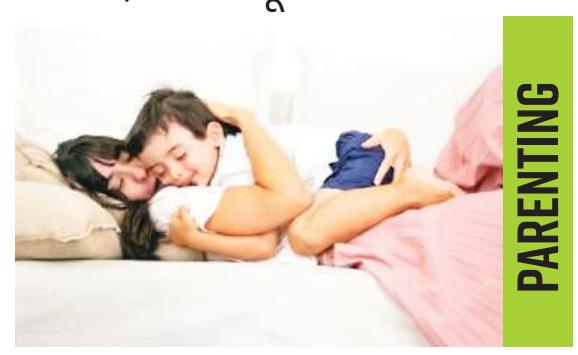

जालंधर ब्रीज (फीचर) . सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है, जिसका असर वयस्कों पर ही नहीं बल्कि छोटे बच्चों की आदतों में भी देखने को मिल रहा है। स्कूली बच्चे जहां गर्मियों में मम्मी की एक आवाज पर बिस्तर छोड़ दिया करते थे, वहीं घड़ी का अलार्म बंद होने के बाद भी कंबल छोड़ने के लिए राजी नहीं होते हैं। नतीजा रोज-रोज स्कूल पहुंचने में देरी का होना। अगर आपके घर के बच्चों का हाल भी कुछ ऐसा है तो ये पेरेंटिंग टिप्स आपकी बहुत मदद करने वाले हैं। आइए जानते हैं बच्चों को खुशी-खुशी सुबह स्कूल के लिए उठाने के लिए अपनाने होंगे कौन से मजेदार टिप्स।

स्कूली बच्चे को सुबह उठाने के लिए अपनाएं ये टिप्स

रात को ही करके रखें 80 प्रतिशत तैयारी : पेरेंट्स को चाहिए कि वो रात को ही सोने से पहले बच्चे की स्कूल यूनिफॉर्म इस्त्री करके, बैग लगाकर , पानी की बोतल भरकर, जूते पॉलिश करके बेड के पास रख दें। ऐसा करने से सुबह 'कहां है ये-वो' की भागदौड़ और टेंशन से बच्चा ही नहीं आप भी बचे रहेंगे। इसके अलावा यह तैयारी बच्चे को 10-15 मिनट देर तक सोने की राहत भी देती है।

बच्चे के अलार्म से पहले पेरेंट्स का अलार्म बजे : आप बच्चे से हमेशा 15-20 मिनट पहले उठें, गुनगुना पानी पिएं, रूम हीटर या ब्लोअर चालू करें। कमरे का तापमान 22-24°c हो जाए तो बच्चे को उठाना आसान हो जाता है।

रजाई में ही 'गर्म हग या गुदगुदी' का अटैक कर दें : सुबह बच्चे को स्कूल के लिए उठाते समय सबसे पहले उसकी रजाई मत हटाएं बल्कि रचाई के अंदर घुसकर उसे गले लगाएं। कान में प्यार से कुछ बोलो या गुदगुदी करो। 2-3 मिनट में बच्चा हंसते-हंसते उठ जाता है।

धीरे-धीरे उठाएं, अचानक नहीं : बच्चों को कभी भी अचानक आकर जगाने की गलती ना करें। ऐसा करने से वे चिड़चिड़े हो जाते हैं। इसकी जगह पहले हल्की आवाज में उसका नाम लें। कमरे के पर्दे खोलकर हल्की रोशनी कमरे में आने दें। उसका पसंदीदा गाना या म्यूजिक प्ले करें।

***डिस्क्लेमर :** इस लेख में दी गई सूचना पूरी तरह सोशल मीडिया रील पर आधारित है। जालंधर ब्रीज इसकी सत्यता और सटीकता की जिम्मेदारी नहीं लेता है।*

सिलेब्रिटीज क्यों सुबह खाली पेट लेते हैं 1 चम्मच घी? न्यूट्रीशनिस्ट ने बताए फायदे!

Health जाह्नवी कपूर, शिल्पा शेट्टी और कृति सेनन जैसे कई सिलेब्रिटीज अपने दिन की शुरुआत एक चम्मच देसी घी के साथ करते हैं। न्यूट्रीशनिस्ट शिखा गुप्ता कहती हैं कि ये छोटी सी आदत हेल्थ पर बड़ा असर डालती है...

• **जालंधर ब्रीज.** हेल्थ केयर

बॉलीवुड सिलेब्रिटीज की फिटनेस अक्सर लोगों के बीच चर्चा का विषय रहती है। वो क्या खाते हैं, क्या रूटीन फॉलो करते हैं, हर कोई ये जानना चाहता है। आज हम सिलेब्रिटीज के पॉपुलर मॉर्निंग रिचुअल के बारे में बात करेंगे। दरअसल जाह्नवी कपूर, शिल्पा शेट्टी और कृति सेनन जैसे कई सिलेब्रिटीज अपने दिन की शुरुआत एक चम्मच देसी घी के साथ करते हैं। न्यूट्रीशनिस्ट शिखा गुप्ता कहती हैं कि ये छोटी सी आदत हेल्थ पर बड़ा असर डालती है। अगर आप सुबह उठते ही खाली पेट एक चम्मच देसी घी लेते हैं, तो इसके कई हेल्थ बेनिफिट्स हो सकते हैं। आइए डिटेल में जानते हैं सिलेब्रिटीज के इस पॉपुलर मॉर्निंग रिचुअल के बारे में।

बहुत मायने रखती है सुबह की सही शुरुआत

न्यूट्रीशनिस्ट कहती हैं कि ज्यादातर लोग अपने दिन की शुरुआत चाय या कॉफी के साथ करते हैं। लेकिन आपके हार्मोन, कॉर्टिसोल लेवल और गट कैफीन का घूंट भरने से पहले ही एक्टिव हो जाते हैं। ऐसे में आप उन पहले 5 मिनट में अपनी बॉडी को क्या दे रहे हैं, ये दिन भर के लिए आपके एनर्जी लेवल, मूड और डाइजेशन को तय करता है। यही वजह है कि अगर आप सुबह घी लेने से शुरुआत करते हैं, तो इस छोटी सी हैबिट का भी बड़ा असर होता है।

सुबह खाली पेट घी लेने से क्या होगा?

सुबह खाली पेट घी लेना आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इससे पेट में एक तरह की कोटिंग बन जाती है, जिस वजह से ब्लोटिंग और एसिडिटी कम होती है और पाचन बेहतर होता है। ये इंसुलिन स्टेबिलिटी को इंप्रूव करता है, जिससे क्रेविंग भी कम होती है और एनर्जी भी बनी रहती है। ये स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल के लेवल को भी स्टेबलाइज करता है, जिससे एंग्जाइटी में राहत मिलती है। खाली पेट चाय कॉफी पीने से जो कैफीन क्रैश होता है, उसे कम करने में भी मदद करता है।

किस-किस को नहीं लेना चाहिए?

जिन भी लोगों को पित्त की थैली से जुड़ी कोई समस्या है या ग्रेड 3 का फैटी लीवर है, तो उन्हें सुबह घी लेना अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा अगर सुबह घी खाने से आपका जी मिचलाता है, तो भी परहेज करना बेहतर है।

क्या देसी घी लेने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा?

न्यूट्रीशनिस्ट कहती हैं कि ऐसा नहीं है। दरअसल घी में CLA और ब्यूटीरेट होता है, जो फैट मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है और लिवर के फंक्शन को बेहतर बनाता है। एक चम्मच घी आपका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ाता, बल्कि इन्फ्लेमेशन बढ़ाती है।

कैसे लेना है?

देसी घी लेने के कई तरीके हैं। आप सिंपल एक चम्मच घी को पिघलाकर खा सकते हैं, इसके अलावा गर्म पानी में मिलाकर भी पी सकते हैं। बेहतर बनाने के लिए जरा सी हल्दी और काली मिर्च में घी मिलाकर खाया जा सकता है। सुबह कॉफी या चाय पीते हैं, तो उससे पहले एक चम्मच घी ले लें। कभी भूल जाएं, तो कॉफी या चाय में मिलाकर भी ले सकते हैं।

***

***डिस्क्लेमर :** यह लेख मात्र सामान्य जानकारी के लिए है। किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की राय अवश्य लें।*

2030 तक एचआईवी/एड्स महामारी को समाप्त करना भारत का अगला बड़ा सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसर

• **जालंधर ब्रीज** . नई दिल्ली

भारत एचआईवी/एड्स के खिलाफ अपनी लड़ाई में एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। पहली घटना की रिपोर्ट होने के चार दशकों बाद, देश ने राष्ट्रीय एचआईवी रोकथाम और उपचार कार्यक्रम का निर्माण किया है, जो दुनिया के सबसे व्यापक और मजबूत उपचार कार्यक्रमों में से एक है। राष्ट्रीय एड्स और एसटीडी नियंत्रण कार्यक्रम (एनएसीपी) ने निर्विवाद उपलब्धियाँ हासिल की हैं। नई संक्रमण दर 2010 की तुलना में लगभग आधी रह गई है, एड्स से संबंधित मृत्यु दर में 80% की कमी दर्ज की गयी है, उपचार पर रहने वाले लोगों में वायरस नियंत्रण अब 97% से अधिक है और भारत ने पूरी तरह से डोल्यूटेग्राविर-आधारित उपचार योजनाओं को अपनाने के साथ बड़ा बदलाव किया है—जिससे यह उपचार प्रभावकारिता में विश्व के अग्रणी देशों में शामिल हो गया है।

हालांकि, आत्मसंतुष्टि की कोई जगह नहीं हो सकती। देश 2026-31 के लिए एनएसीपी चरण-VI (एनएसीपी VI) में प्रवेश कर रहा है, लेकिन इसके साथ ही यह सच्चाई भी स्वीकार करनी होगी कि भारत में महामारी अभी भी विकसित हो रही है और कुछ जगहों पर यह तेजी से बढ़ रही है। महामारी की मौजूदगी का राष्ट्रीय औसत केवल 0.20% है, लेकिन यह उभरते हुए हॉटस्पॉट और नई कमजोर स्थितियों को छिपाता है। असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और पंजाब जैसे राज्यों में मुख्य रूप से सुई से नशीली दवाओं के सेवन के कारण घटनाओं के बढ़ने की रिपोर्ट मिली है। सुई से नशीली दवा लेने वाले लोगों में, एचआईवी होने की दर राष्ट्रीय औसत से चालीस गुना अधिक है और कुछ ख़ास स्थानों में इसमें गुणात्मक वृद्धि देखी जा रही है। एक ही सुई साझा करने की घटना से संक्रमण का अनुमानित 1-में-160 मौका होने के कारण, सुई से नशीली दवाओं के सेवन से जुड़ी एचआईवी महामारी तेजी से फैल सकती है, यदि इसके खिलाफ प्रभावी ढंग से जवाबी कारवाई नहीं की जाती है।

इसके अलावा, नए संक्रमणों का बढ़ता हुआ हिस्सा अब उन व्यक्तियों में देखने को मिल रहा है जो अपने आकस्मिक या नियमित साथियों से एचआईवी प्राप्त कर रहे हैं—जो पारंपरिक 'मुख्य जनसंख्या' से परे बदलाव का संकेत देता है। भारत की युवा जनसांख्यिकी - हर साल 15-25 आयु वर्ग में 2.25 करोड़ किशोर प्रवेश कर रहे हैं - संवेदनशील बनी हुई है, क्योंकि डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म तक आसान पहुँच जोखिम से भरे यौन व्यवहार और मादक पदार्थों के उपयोग को बढ़ावा देती है। भारत ने ऊर्ध्वाधर मातृ-शिशु संचरण को कम करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। गर्भवती माताओं के लिए एचआईवी और सिफ़लिस की सार्वभौमिक जांच और उपचार, शिशु का प्रारंभिक निदान और बालरोग निवारक उपायों ने माताओं से बच्चों में संचरण को 2020 के 25% से अधिक से कम करके 2024 में 10% तक कर दिया है। फिर भी, यह उन्मूलन की पांच प्रतिशत सीमा से ऊपर है।

वी हेकाली झीमोमी
(स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की अपर सचिव और राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (एनएसीओ) की महानिदेशक)

सीधे तौर पर कहें तो, वायरस ने खुद को अनुकूलित कर लिया है। यह युवाओं को प्रभावित करता है, अधिक फैलाव वाला है और नई कमजोरियों का फायदा उठा रहा है। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए एक नई रणनीति की आवश्यकता है। एनएसीपी-VI की परिकल्पना भारत की सबसे साहसी और सबसे भविष्य-अनुकूल एचआईवी रणनीति के रूप में की गयी है। यह 2030 तक एड्स को सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे के रूप में समाप्त करने के लक्ष्य (एस डी जी 3.3) के अनुरूप है—और यह चार बड़े बदलावों में निहित है।

सबसे पहले, भारत की विविध संवेदनशीलता प्रोफ़ाइल यह मांग करती है कि रोकथाम को श्रेणियों के बजाय लोगों के अनुसार बदला जाए। पारंपरिक 'उच्च-जोखिम समूहों' से अलग, कार्यक्रम को सामाजिक और संरचनात्मक कारकों द्वारा पैदा होने वाली तथा एक-दूसरे से जुड़ी कमजोरियों को संबोधित करना होगा। संपूर्ण सुरक्षा रूपरेखा के तहत, सार्वभौमिक रोकथाम यह सुनिश्चित करेगी कि हस्तक्षेप, समूहों के बजाय जोखिम वाले व्यक्तियों तक पहुंचे। एआई-संचालित स्वयं जोखिम आकलन, वर्चुअल पहुंच, नए दवा उपकरण और हॉटस्पॉट या सबसे ज्यादा संक्रमण फैलाने वाले संभावित लोगों (सुपर-स्प्रेडर) का पता लगाने के लिए रोग निगरानी प्लेटफ़ॉर्म, रोकथाम और सेवाओं को आपस में जोड़ने के अगली पीढ़ी के प्रयासों को सशक्त करेंगे। छह नशीली दवाओं के उपयोग से उत्पन्न महामारियों पर लक्षित रणनीतियाँ, एनएसीपी-VI के तहत महामारी को तेजी से कम करने के लिए केंद्रीय होंगी।

दूसरा, एनएसीपी-VI को जल्दी पहचान, प्रभावी इलाज, जीवन भर बनाए रखने के दृष्टिकोण पर आधारित होना चाहिए। उच्च गुणवत्ता वाले, मुफ्त एंटीरिट्रोवायरल उपचार और वायरल-कमी (वायरल सप्रेशन) को बढ़ाने में भारत की सफलता अभूतपूर्व है। फिर भी, उपचार का पालन करने और प्रारंभिक निदान के लिए रोगियों को बनाए रखने का काम अभी भी जारी है। आभा, टेलीमेडिसिन और एआरटी वितरण के लिए डिजिटल फॉलो-अप का उपयोग करते हुए आपस में जुड़े तरीके सेवा अदायगी बाधाओं को दूर करने में मदद करेंगे। आभा और आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के साथ एनएसीपी-VI का एकीकरण, एचआईवी देखभाल को व्यापक सार्वजनिक स्वास्थ्य इकोसिस्टम की मुख्य-धारा में लाने का मौका देता है।

तीसरा, एचआईवी और सिफ़लिस के ऊर्ध्वाधर संचरण को समाप्त करना एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनिवार्यता है। आरएमएनसीएच+ए के साथ तालमेल बढ़ाकर, निजी क्षेत्र से डेटा-प्रवाह और जांच किट्स के लिए विकेंद्रीकृत आपूर्ति श्रृंखलाओं के माध्यम से, भारत 2030 तक उन्मूलन का लक्ष्य हासिल कर सकता है। हालांकि, इसके लिए हर गर्भवती महिला तक—स्थान, जाति, आय या वैवाहिक स्थिति की परवाह किए बिना—पहुंचना आवश्यक है।

चौथी बात, कार्यक्रम को कलंक समाप्त करने पर अपने जोर को फिर से शुरू करना चाहिए। कलंक अदृश्यता, देरी से निदान और गैर-उपचार संक्रमण का सबसे बड़ा कारण है। एचआईवी और एड्स (रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 2017; एचआईवी और एड्स से संक्रमित और प्रभावित लोगों के लिए अधिकार-आधारित कानून है। यह अधिनियम कलंक और भेदभाव से मुक्त वातावरण में सेवा प्राप्त करने को प्रोत्साहित करता है। फिर भी यह कलंक घरों, अस्पतालों, कार्यस्थलों और यहां तक कि नीतियों में भी मौजूद है और इससे निपटने के लिए मजबूत और लगातार प्रयास करने की आवश्यकता है।

एचआईवी रोकथाम में भारत की यात्रा कई साहसिक उपलब्धियों से परिपूर्ण रही है। एचआईवी नियंत्रण और रोकथाम में शुरूआती निवेश ने महामारी की दिशा को पलटने में मदद की, जिससे एक पूरी पीढ़ी को पीड़ा और रुग्णता से बचाया गया। इसके परिणामस्वरूप एक स्वस्थ जनसांख्यिकीय लाभ हुआ, जो आर्थिक विकास में योगदान देता है। बड़े पैमाने पर सेवा वितरण में स्पष्ट उपलब्धियों का एनएसीपी का ट्रैक रिकॉर्ड अंतिम प्रयास के लिए आधार मजबूत करता है। अब विज्ञान, पहले से कहीं अधिक भारत के एचआईवी/एड्स उन्मूलन विज़न के पक्ष में है। हमारी जैव प्रौद्योगिकी और दवा उद्योग की क्षमता दवाओं, वैक्सीन और डायग्नोस्टिक्स का तेजी से विकास कर सकती है और पैमाने का तेज विस्तार कर सकती है, जिससे उन्मूलन प्रयासों के लिए सहायता मिलती है।

फिर भी, हजार मील की यात्रा में, आखिरी मील हमेशा सबसे कठिन होता है। एचआईवी/एड्स को एक सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे के रूप में समाप्त करने की आखिरी कोशिश केवल जैव-चिकित्सीय नहीं है—यह सामाजिक, डिजिटल, व्यवहारिक और संरचनात्मक भी है। एनएसीपी-VI एक आगामी रोडमैप प्रदान करता है, जो तकनीकी रूप से आधुनिक, महामारी विज्ञान के दृष्टिकोण से सटीक और सामाजिक रूप से जमीन से जुड़ा है। अडिग सरकारी प्रतिबद्धता और एक सुदृढ़ सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के समर्थन के साथ, भारत इस अवसर का साहसपूर्वक लाभ उठाएगा—दुनिया को यह दिखाने के लिए कि जब विज्ञान, समुदाय और नीति मिलकर कार्य करते हैं, तो एक महामारी को समाप्त करना संभव है।

फर्जी खबरें लोकतंत्र के लिए ख़तरा: सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव

जालंधर ब्रीज (नई दिल्ली) . केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में बताया कि सोशल मीडिया और फर्जी खबरों से जुड़ा मुद्दा बेहद गंभीर है। उन्होंने कहा कि फर्जी खबरें लोकतंत्र के लिए खतरा हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, गलत सूचनाओं और एआई-जनित डीपफेक पर सख्त कार्रवाई की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग या समूह जिस तरह से सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं उससे लगता है कि ये भारत के संविधान या संसद द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन नहीं करना चाहते। उन्होंने इस मामले सख्त कार्रवाई और कड़े नियम बनाने की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया।

वैष्णव ने संसद में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए बताया कि हाल ही में नए नियम लागू किए गए हैं, जिनमें छत्तीस घंटों के भीतर वीडियो हटाने का प्रावधान भी शामिल है। एआई-जनित डीपफेक की

अश्विनी वैष्णव
(केंद्रीय सूचना और प्रसारण)

पहचान करने और उन पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए एक मसौदा नियम भी प्रकाशित किया गया है और इस पर विचार-विमर्श चल रहा है। उन्होंने संसदीय समिति के कार्य की सराहना की और कानूनी ढांचे को मजबूत करने के लिए प्रमुख सिफारिशों वाली एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए निशिकांत दुबे और सभी सदस्यों को धन्यवाद दिया।

सूचना और प्रसारण मंत्री ने कहा कि फर्जी खबरें तथा सोशल मीडिया से जुड़े मुद्दों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता व हमारे लोकतंत्र की सुरक्षा के बीच एक नाज़ुक संतुलन की आवश्यकता है और सरकार इस संतुलन को बनाए रखने के लिए पूरी संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, डिजिटल इंडिया पहल ने एक बड़ा बदलाव लाया है और तकनीक का लोकतांत्रिकरण किया है जिसके सकारात्मक प्रभावों को स्वीकार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया ने भी प्रत्येक नागरिक को एक मंच प्रदान किया है। इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, सरकार संस्थाओं और समाज की नींव रखने वाले विश्वास को मज़बूत करने के लिए काम कर रही है।

आपकी पूंजी -आपका अधिकार" अभियान के तहत शहीद भगतसिंह नगर एवं तरन तारण में विशाल शिविर लगाया गया

जालंधर ब्रीज (नई दिल्ली) . भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, द्वारा जारी "आपकी पूंजी -आपका अधिकार" जन जागरण अभियान जो कि 1 अक्टूबर 2025 से 31 दिसम्बर 2025 तक चलाया गया है, जिसके तहत अग्रणी जिला प्रबंधकों द्वारा सभी वित्तीय संस्थाओ से संपर्क करते हुए भारत सरकार एवं भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा निर्देशानुसार शिविर लगाये जा रहे है।

इसी के तहत शहीद भगतसिंह नगर एवं तरन तारन में विशाल शिविर का आयोजन 5 दिसम्बर 2025 को किया गया। जिसमें बैंक, बीमा, पेंशन एवं म्युचुअल फंड विभागों के शीर्ष अधिकारियों द्वारा भाग लिया गया। पंजाब नेशनल बैंक एवं राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति पंजाब के उप महाप्रबंधक रामकिशोर मीना द्वारा बताया गया कि वित्त मंत्रालय द्वारा जारी "आपकी पूंजी -आपका अधिकार" जन जागरण अभियान के तहत अभी तक पंजाब के 18 जिलो में विशाल कैम्प लगाये जा चुके हैं एवं सांतवे चरण में शहीद भगतसिंह नगर एवं तरन तारन में विशाल शिविर का

रामकिशोर मीना
(पंजाब नेशनल बैंक एवं राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति पंजाब के उप महाप्रबंधक)

आयोजन किया जायेगा।

उन्होंने आगे बताया कि शहीद भगतसिंह नगर में 233958 खातो में 112.08 करोड़ एवं एवं तरन तारन में 268312 खातो में 82.31 करोड़ राशी बिना दावे के पड़ी हुई हैं.उन्होंने आगे बताया की बैंक में जमा राशि को यदि देय तिथि के तक प्राप्त नहीं किया गया हो तो या जमा खातो में लेन देन बंद कर देने पर खाता निष्क्रिय हो जाता है एवं यह जमा राशि 10 वर्ष बाद भारतीय रिज़र्व बैंक को चली जाती है। इसी तरह म्यूच्यूअल फण्ड एवं बीमा में निवेश की गयी राशी को भी परिपक्वता तिथि पर प्राप्त करना जरुरी है . जिस जमा राशी को अभी तक देय तिथि निकल जाने के बावजूद भी प्राप्त नहीं किया गया, इस दावा रहित पुरानी जमा राशि, म्युचुअल फंड, बीमा राशि, को कैसे प्राप्त किया जा सकता, इसकी विस्तृत जानकारी शिविर में दी जाएगी।

इस तरह के जागरूकता शिविर सभी राज्यों में लगाये जा रहे है ताकि पुरानी दावा रहित जमा राशी को वापस उसके असली मालिक को या नामित व्यक्ति को या कानूनन उत्तराधिकारियों को वापस की जा सके। अधिक जानकारी हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक के उदगम पोर्टल (Udgam Portal) एवं अपनी नजदीकी बैंक शाखा में संपर्क कर सकते है एवं अपनी पुरानी जमा राशी को प्राप्त कर सकते हैं। शिवर के दौरान ग्राहक अपने खाते में पुन के वाई सी एवं नामांकन भी अद्दतन करवा सकते हैं।

प्रत्येक महिला को सशक्त बनाना, प्रत्येक समुदाय का उत्थान करना-अमृत काल में नारी शक्ति का नया दौर

जालंधर ब्रीज (नई दिल्ली) . जब महिलाएं आगे बढ़ती हैं, तो राष्ट्र का उत्थान होता है। समानता और न्याय के मूल्यों पर आधारित समाज में, महिला की गरिमा से कतई समझौता नहीं होना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तिकरण के लिए हमारे समग्र कार्यक्रम- मिशन शक्ति- के ज़रिए इसे संस्थागत ढांचे में बदलकर इस विश्वास को फिर से मजबूत किया है। जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने उचित ही कहा है, "हमारी सरकार महिलाओं के लिए 'सम्मान' और 'सुविधा' को सबसे ज़्यादा महत्व देती है।'' ये मार्गदर्शक शब्द केवल भावनाएँ मात्र नहीं, अपितु वह नींव हैं, जिस पर मोदी सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए मिशन शक्ति के तहत भारत के कोने-कोने में मज़बूत संस्थागत तंत्र स्थापित किए हैं।

इस प्रयास के केंद्र में मिशन शक्ति की "संबल'' उप-योजना के तहत चलने वाले वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) हैं। 2015 में शुरू हुए ये केंद्र हिंसा की शिकार महिलाओं को एकीकृत सहायता तंत्र प्रदान करते हैं, ताकि उन्हें खामोश रहकर पीड़ा न सहनी पड़े और न ही बिखरी हुई सहायता प्रणालियों के बीच भटकना पड़े। आज तक, पूरे भारत में 862 ओएससी चल रहे हैं, जिनसे 12.20 लाख से ज़्यादा महिलाओं को एक ही छत के नीचे कानूनी मदद, चिकित्सा सहायता, पुलिस की मदद, आश्रय और मनोवैज्ञानिक परामर्श जैसी एकीकृत मदद मिली है।

डर से आज़ादी तक, खामोशी से सहायता तक - ओएससी ऐसे स्थान हैं जहाँ से घाव भरने की शुरूआत होती है। ये केंद्र प्रतिक्रियात्मक शासन से आगे बढ़कर सक्रिय शासन का रुख करते हैं। चाहे किसी महिला को अपने घर, कार्यस्थल या सार्वजनिक स्थान पर हिंसा का सामना करना पड़े, ओएससी उसके पुनर्वास, गरिमा और न्याय दिलाने में मदद करने के मोदी सरकार के संकल्प का प्रमाण हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये केंद्र अस्पतालों के भीतर या उनके पास स्थापित किए गए हैं, ताकि तुरंत चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जा सके - जो मुश्किल समय में पहला ज़रूरी कदम है। महिला हेल्पलाइन (181) का सार्वभौमीकरण भी उतना ही महत्वपूर्ण है, जो संकट से घिरी महिलाओं के लिए 24x7 मदद सुनिश्चित करके ओएससी का पूरक बनता है। 35 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में संचालित यह हेल्पलाइन अब तक 2.56 करोड़ से अधिक कॉल संभाल चुकी है और 93.48 लाख से अधिक महिलाओं की मदद कर चुकी है (30 सितंबर तक)। आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ईआरएसएस-112) से एकीकृत यह हेल्पलाइन संकट और राहत के बीच की दूरी को पाटती है।

व्यवस्थागत जवाबदेही को मजबूत करने और तेजी से न्याय पहुंचाने के लिए, हमने 745 फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय स्थापित किए हैं, जिनमें से 404 विशेष पॉक्सो न्यायालय हैं। इन न्यायालयों ने यह सुनिश्चित करते हुए कि न्याय में देरी का मतलब न्याय से इनकार नहीं है, अब तक 3.06 लाख से अधिक मामलों का निपटारा किया है। सुनाया गया प्रत्येक फ़ैसला, बहाल किया गया प्रत्येक अधिकार न्यायपूर्ण और लैंगिक समानता वाले भारत की ओर उठाया गया एक कदम है। न्याय मिलना अब प्रक्रियात्मक देरी के कारण बाधित नहीं होता, और प्रत्येक सर्वाइवर समय पर राहत की उम्मीद कर सकता है। इसके साथ ही, हम पुलिस स्टेशनों पर 14,658 महिला हेल्प डेस्क (डब्ल्यूएचडी) के साथ ज़मीनी स्तर को मज़बूत कर रहे हैं, जिनमें से 13,700 से ज़्यादा की कमान महिलाएँ संभाल रही हैं। ये डेस्क सर्वाइवर्स में अपराधों की रिपोर्ट करने का आत्मविश्वास बढ़ाते हैं, जिन्हें महिलाओं से संबंधित मुद्दों के प्रति संवेदनशील प्रशिक्षित कार्मिकों की सहायता मिलती है। महिला अधिकारियों की मौजूदगी न केवल आत्मविश्वास बढ़ाती है, बल्कि संस्थागत संवेदनशीलता और जवाबदेही को भी मज़बूत करती है।

अन्नपूर्णा देवी
(लेखिका भारत सरकार में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं।)

हम 807 एंटी-ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स (एएचटीयू) के ज़रिए मानव तस्करी से भी निपट रहे हैं और निर्भया कोष के तहत रेलवे और सड़क परिवहन सेवाओं में आपातकालीन निगरानी प्रणालियों की स्थापना के जरिए सुरक्षित गतिशीलता सुनिश्चित कर रहे हैं। ये कदम कि महिलाओं का सुरक्षित रूप से यात्रा करना, निडर होकर काम करना और सार्वजनिक एवं निजी जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रगति करना सुनिश्चित करते हैं। यह एकीकृत दृष्टिकोण सिर्फ़ प्रतिक्रिया तक ही सीमित नहीं है, बल्कि रोकथाम, पुनर्वास और सशक्तिकरण तक व्याप्त है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) जैसी पहलों के ज़रिए, हम सोच बदल रहे हैं और सम्मान, बराबरी और अवसर के मूल्य स्थापित कर रहे हैं। पीएमएमवीवाई और सखी निवास के ज़रिए, हम ऐसी व्यवस्थाएं बना रहे हैं, जो महिलाओं को सिर्फ़ सर्वाइवर के तौर पर ही नहीं, बल्कि देश की प्रगति में हितधारकों के तौर पर भी महत्व देती हैं। हमारे सखी निवास हॉस्टल, जिनमें से कई शहरी प्रत्येक और अर्ध-शहरी इलाकों में हैं,- 26,000 से ज़्यादा कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित और किफायती रहने की जगह दे रहे हैं जिससे वे बिना किसी डर के अपने सपने पूरे कर सकती हैं।

मिशन शक्ति के तहत हमारी रणनीति एकीकरण, समन्वय और सामुदायिक स्वामित्व पर आधारित है। संकल्प: हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ़ विमेन की शुरुआत के साथ, हमने स्थानीय क्रियान्वयन में एक रणनीतिक परत जोड़ी है, जिससे महिलाएँ एक ही प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से कई योजनाओं का लाभ ले सकती हैं। स्थानीय स्तर पर सशक्तिकरण और समन्वय के केंद्र के रूप में कार्य करने वाले इन केंद्रों के ज़रिए 27 लाख से ज़्यादा महिलाएं लाभान्वित हो चुकी हैं। महिलाओं के खिलाफ हिंसा केवल महिलाओं का मुद्दा नहीं है, यह एक राष्ट्रीय सरोकार है।

यूआईडीएआई ने नवंबर में 231 करोड़ आधार प्रमाणीकरण लेनदेन दर्ज किए, नवंबर 2024 की तुलना में 8.47 प्रतिशत की वृद्धि

जालंधर ब्रीज (नई दिल्ली) . आधार संख्या धारकों ने नवंबर 2025 में 231 करोड़ प्रमाणीकरण लेनदेन किए, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में लगभग 8.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। यह आधार के बढ़ते उपयोग के साथ-साथ देश में डिजिटल अर्थव्यवस्था के विकास का भी संकेत है। नवंबर 2025 में प्रमाणीकरण लेनदेन इस वित्तीय वर्ष के किसी भी पिछले महीने की तुलना में अब तक के सबसे अधिक हैं। अक्टूबर में यह संख्या 219.51 करोड़ थी। बढ़ते उपयोग से पता चलता है कि किस प्रकार आधार प्रभावी कल्याणकारी योजनाओं के वितरण में सूत्रधार की भूमिका निभा रहा है और सेवा प्रदाताओं द्वारा दी जाने वाली सेवाओं का स्वेच्छा से लाभ उठा रहा है।

आधार चेहरा प्रमाणीकरण समाधानों में भी लगातार वृद्धि देखी जा रही है। नवंबर के दौरान पेंशनभोगियों द्वारा जारी किए गए लगभग 60 प्रतिशत डिजिटल जीवन प्रमाणपत्रों में आधार चेहरा प्रमाणीकरण का उपयोग किया गया। यूआईडीएआई का यह एआई आधारित चेहरा प्रमाणीकरण तरीका एंड्रॉइड और आईओएस दोनों प्लेटफॉर्म पर काम करता है। यह उपयोगकर्ताओं को केवल एक फेस स्कैन से अपनी पहचान सत्यापित करने में सक्षम बनाता है, जिससे सुविधा सुनिश्चित होती है और साथ ही कड़े सुरक्षा मानकों का पालन भी होता है। कुल मिलाकर, नवंबर 2025 में 28.29 करोड़ चेहरा प्रमाणीकरण लेनदेन किए गए, जबकि 2024 में इसी अवधि के दौरान ऐसे लेनदेन 12.04 करोड़ थे। इसी प्रकार, नवंबर के दौरान ई-केवाईसी लेनदेन में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई। महीने के दौरान 47.19 करोड़ ऐसे लेनदेन दर्ज किए गए, जो नवंबर 2024 की तुलना में 24 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि है। आधार ई-केवाईसी सेवा ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाने और बैंकिंग तथा गैर-बैंकिंग वित्तीय सेवाओं सहित क्षेत्रों में व्यापार में सुगमता बढ़ाने में उत्प्रेरक बनी हुई है।

60 वर्ष पूर्ण होने पर बीएसएफ ने स्थापना दिवस का आयोजन कर स्थापना की हीरक जयंती मनाई

सतीश एस खंडारे ने बीएसएफ की उपलब्धियों और भारत सरकार द्वारा बीएसएफ के सेवारत और सेवानिवृत कर्मचारियों के लिए शुरू की गई कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी।

जालंधर ब्रीज (चंडीगढ़) . मुख्यालय विशेष महानिदेशक, सीमा सुरक्षा बल चंडीगढ़ ने दोनों कैंपस (बी एस एफ कैंपस लखनौर, मोहाली और इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-2, चंडीगढ़) में सीमा सुरक्षा बल हीरक जयंती का आयोजन किया गया।

इससे पहले, 21 नवंबर 2025 को, बल मुख्यालय ने 176 बटालियन, सीमा सुरक्षा बल कैंपस भुज, गुजरात में हीरक जयंती वर्ष कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया, जिसकी अध्यक्षता भारत के माननीय केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने की। इस दौरान मुख्य अतिथि ने बल के जवानों को वीरता पुरस्कार, विशिष्ट सेवा हेतु राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया। आयोजन के दौरान स्काई डाइविंग और ड्रोन शो का आकर्षण का केंद्र रहे।

सतीश एस खंडारे, भारतीय पुलिस सेवा, अपर महानिदेशक ने पश्चिम कमान के सभी सीमा प्रहरियों के साथ राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी और देश की सुरक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले शहीदों को हृदय से श्रद्धांजलि दी।

इसके बाद, अपर महानिदेशक ने लखनौर कैंपस में एक प्रेस ब्रीफिंग की। राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मीडिया प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना 01 दिसंबर 1965 को 'रक्षा की प्रथम पंक्ति ' के तौर पर 25 बटालियन के साथ हुई थी, जो अब बढ़कर 193 बटालियन हो गई है एवं पाकिस्तान व बांग्लादेश के साथ कुल 6386 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर की सुरक्षा कर रही है। सीमा सुरक्षा बल की पश्चिमी कमान भारत-पाक बॉर्डर पर 2289.66 किलोमीटर की सुरक्षा कर रहा है। यह बल विश्व का सबसे बड़ा सीमा को सुरक्षा प्रदान करने वाला बल है, जिसमें एयर-विंग, वॉटर विंग और आर्टिलरी रेजिमेंट है, साथ ही 2.76 लाख से ज्यादा बहादुर पुरुष और महिलाओं को सुरक्षा प्रदान कर रहा है। जहां तक पश्चिमी कमान की बात है, यह 05 फ्रंटियर्स यानी कश्मीर, जम्मू, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के अलावा 03 सहायक प्रशिक्षण केन्द्र के साथ भारत-पाकिस्तान बॉर्डर पर प्रभावशाली सीमा प्रबंधन के लिए उत्तरदायी है।

दुर्गम इलाके और खराब मौसम के बावजूद, सीमा सुरक्षा बल जवान, घुसपैठ, नशीले पदार्थों, हथियारों, गोला-बारूद की तस्करी जैसे सीमा-पार अपराधों को असरदार तरीके से रोक रहा है। दुश्मन के नापाक इरादों को असफल करने के लिए सीमा सुरक्षा बल की कोशिशों पर रोशनी डालते हुए, अपर महानिदेशक ने मीडिया को विभिन्न ऑपरेशन और उनकी कामयाबियों से अवगत कराया और कहा कि धुंध के मौसम को देखते हुए, सीमा सुरक्षा बल ने असामाजिक तत्वों की गतिविधियों को रोकने और देश के दुश्मनों से सीमाओं की रक्षा करने के लिए अपनी चैकसी और बढ़ा दी है।

महिला पुलिस को मुख्य धारा में लाने के लिए राज्य-व्यापी प्रशिक्षण परियोजना शुरू

पीपीए फिल्लौर में ट्रेनर्स के प्रशिक्षण (टीओटी) कार्यक्रम के तहत पहले चरण का प्रशिक्षण पूरा, कुल 384 पुलिस स्टेशनों को किया जाएगा कवर, पुलिस बल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए क्षमता निर्माण हेतु 2000 पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जाएगा: विशेष डीजीपी गुरप्रीत देव

• **जालंधर ब्रीज.** चंडीगढ़

पंजाब पुलिस द्वारा एक ऐतिहासिक पहल में "मेनस्ट्रीमिंग ऑफ वूमन पुलिस" प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य पूरे राज्य में महिला पुलिस अधिकारियों की भूमिका और एकीकरण का व्यापक मूल्यांकन करना और इसे और बेहतर बनाना है। यह प्रोजेक्ट 2 से 4 दिसंबर 2025 तक पंजाब पुलिस अकादमी (पीपीए), फिल्लौर में आयोजित तीन दिवसीय ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स (टीओटी) कार्यक्रम के साथ शुरू किया गया।

टीओटी प्रोग्राम पंजाब पुलिस के कम्युनिटी अफेयर्स डिवीजन (सीएडी) विंग द्वारा हर्टेक फाउंडेशन की साझेदारी में आयोजित किया गया था। इस दौरान लगभग 60 मास्टर ट्रेनर्स को प्रशिक्षण दिया गया, जिनमें पंजाब के 13 जिलों से आए चार वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी शामिल थे। अब ये अधिकारी अपने-अपने जिलों में प्रशिक्षण देने के लिए जिम्मेदार होंगे।

प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में पुलिस की व्यक्तित्व निर्माण, लैंगिक संवेदनशीलता, वंचित वर्गों को न्याय दिलाने में पुलिस की भूमिका और पारंपरिक रूप से पुरुष-प्रधान पुलिस बल में महिला अधिकारियों को मुख्यधारा में लाने संबंधी रणनीतियाँ शामिल थीं। साथ ही पुलिस में पेशेवर रूप से महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने हेतु वरिष्ठ अधिकारियों की जिम्मेदारियों पर विशेष जोर दिया गया। इस पहल के महत्व के बारे में बोलते हुए विशेष डीजीपी, कम्युनिटी अफेयर्स डिवीजन (सीएडी) गुरप्रीत कौर दियो ने कहा कि यह अहम प्रोजेक्ट "मेनस्ट्रीमिंग ऑफ वूमन पुलिस" पहल का हिस्सा है, जिसके तहत भारत सरकार की महिला हेल्पडेस्क प्रोजेक्ट की देशव्यापी सफलता के आधार पर पंजाब के सभी 384 पुलिस स्टेशनों में दो-दो महिला अधिकारियों को नियुक्त किया गया है। प्रशिक्षण के प्रभाव के वैज्ञानिक मूल्यांकन को सुनिश्चित करने के लिए पंजाब पुलिस ने गैर-सरकारी संगठन जे-पाल (अब्दुल लतीफ जमील पॉवरटी एक्शन लैब) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं, जो कि रैंडमाइज्ड कंट्रोल्ड ट्रायल (आरसीटी) के माध्यम से नीति विश्लेषण में माहिर है।

इस प्रोजेक्ट के तहत राज्य के 288 पुलिस स्टेशन एक राज्य-स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेंगे, जिसमें सीएडी विंग द्वारा प्रशिक्षित और हर्टेक फाउंडेशन के सहयोग से तैयार किए गए लगभग 100-120 मास्टर ट्रेनर्स पूरे प्रदेश के 288 पुलिस स्टेशनों में प्रशिक्षण देंगे। इसमें समाज में महिलाओं की भूमिका, पुलिस बल में महिलाओं की कम संख्या, लैंगिक रूढ़िवादिता और पुलिसिंग सब-कल्चर से संबंधित जानकारी दी जाएगी।

पुलिसिंग सब-कल्चर में– कानून और व्यवस्था बनाए रखना, अपराध की समझ और रोकथाम, गैंगस्टरों और नशे के सौदागरों से निपटना, आतंकवाद आदि पर विशेष ध्यान दिया गया है। जबकि तुलनात्मक रूप से पुलिस की आवश्यकता वाले उभरते क्षेत्रों जैसे साइबर-अपराध, महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के खिलाफ अपराध, ट्रैफिक मुद्दे, पुलिस व्यवहार व प्रतिक्रिया और पुलिस की व्यक्तित्व– पर कम ध्यान दिया गया है।

राज्य के लगभग 96 पुलिस स्टेशनों को कोई प्रशिक्षण नहीं दिया जाएगा और वे कंट्रोल पुलिस स्टेशन की भूमिका निभाएंगे। इस प्रोजेक्ट के लिए चुने गए 120 मास्टर ट्रेनर्स को फरवरी 2026 में आधुनिक जानकारी के साथ प्रशिक्षित किया जाएगा, जिसके बाद ये मास्टर ट्रेनर्स मार्च से जून 2026 तक तीन चरणों में अपने-अपने जिलों के पुलिस स्टेशनों में चुने गए पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण देंगे।

विशेष डीजीपी ने कहा कि पुलिस स्टेशनों में प्रशिक्षण शुरू होने से पहले जे-पाल द्वारा सभी 288 पुलिस स्टेशनों में महिला पुलिस कर्मचारियों के प्रति दूसरे पुलिस कर्मियों के विचारों, धारणा और लिंग-संवेदनशीलता संबंधी बेसलाइन सर्वेक्षण किया जाएगा।

जिला प्रशिक्षण समाप्त होने के बाद, जे-पाल उन्हीं पुलिस उत्तरदाताओं और नागरिकों का एक और सर्वेक्षण करेगा ताकि यह पता लगाया जा सके कि महिला अधिकारियों के प्रति पुलिस अधिकारियों के दृष्टिकोण और लैंगिक मान्यताओं में कितना बदलाव आया है।

बाकी 15 जिलों के मास्टर ट्रेनर्स के लिए दूसरा टीओटी सत्र 22 से 24 दिसंबर 2025 को पीपीए फिल्लौर में आयोजित किया जाएगा।

इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य 2000 से अधिक पुलिस अधिकारियों को सीधे प्रशिक्षण देकर पंजाब में एक बेहतर और प्रभावी पुलिसिंग वातावरण को बढ़ावा देने के लिए संस्थागत क्षमता विकसित करना है।

'सलाखों के पीछे ज़िंदगियों का सशक्तिकरण' के तहत जेलों में स्थापित होंगी 11 आईटीआई

सीजेआई पटियाला की केंद्रीय जेल से ऐतिहासिक पहल की करेंगे शुरुआत, सभी 24 जेलों में 2500 कैदियों को मिलेगा प्रमाणित कौशल प्रशिक्षण

• **जालंधर ब्रीज.** चंडीगढ़

राज्य भर की जेलों में कौशल आधारित पहलों को बढ़ावा देने के लिए पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा जेल विभाग पंजाब तथा तकनीकी शिक्षा एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग पंजाब के सहयोग से एक विशेष कार्यक्रम "सलाखों के पीछे ज़िंदगियों का सशक्तिकरण": जेल न्याय में क्रांतिकारी बदलाव बनाया गया है जिसका उद्घाटन भारत के मुख्य न्यायाधीश, श्री न्यायमूर्ति सूर्या कांत द्वारा 6 दिसंबर 2025 को सेंट्रल जेल, पटियाला में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में किया जाएगा।

यह पहल पंजाब की जेलों को शिक्षा और पुनर्वास केंद्रों में बदलने का एक अनूठा प्रयास है। इसके तहत पंजाब स्किल डिवेलपमेंट मिशन के सहयोग से राज्य की सभी 24 जेलों में लगभग 2,500 कैदियों को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त वोकेशनल ट्रेनिंग प्रदान की जाएगी। इस पहल का मुख्य उद्देश्य जेलों के अंदर कुल 11 आई.टी.आई. की स्थापना करना है, जिनमें वेल्डिंग, इलेक्ट्रीशियन, प्लंबिंग, सिलाई तकनीक, कॉस्मेटोलॉजी, सीओपीए तथा बेकरी जैसी ट्रेडों में एनसीवीटी मान्यता प्राप्त दीर्घकालीन कोर्स कराए जाएंगे। इसके साथ ही टेलरिंग, जूट एवं बैग निर्माण, बेकरी, प्लंबिंग, मशरूम खेती, कंप्यूटर और अन्य कौशलों में एनएसक्यूएफ-अनुकूल अल्पकालिक कोर्स भी शामिल किए जाएंगे।

इस अवसर पर पंजाब राज्य कानूनी सेवाएं प्राधिकरण द्वारा एक महीने की राज्य स्तरीय नशा-विरोधी मुहिम का भी माननीय मुख्य न्यायाधीश द्वारा औपचारिक उद्घाटन किया जाएगा। यह राज्यव्यापी मुहिम 6 दिसंबर 2025 से 6 जनवरी 2026 तक चलेगी, जिसके दौरान जनता को नशों से दूर रहने संबंधी जागरूकता कैंप, कानूनी जागरूकता और पुनर्वास संबंधी जानकारी देने के लिए जनता को जागरूक किया जायेगा।

जालंधर जिले में अंतिम दिन तक जिला परिषद के लिए कुल 114 और पंचायत समितियों के लिए 745 नामांकन दाखिल

जालंधर (जालंधर ब्रीज). पंजाब राज्य चुनाव आयोग द्वारा जारी प्रोग्राम के अनुसार, जालंधर जिले में 14 दिसंबर को आयोजित होने वाली जिला परिषद के 21 और 11 पंचायत समितियों के 188 जोन की चुनावों के लिए नामांकन प्राप्त करने के आज अंतिम दिन जिला परिषद के लिए कुल 114 तथा पंचायत समितियों के लिए कुल 745 नामांकन दाखिल किए गए।

जिला चुनाव अधिकारी-कम -डिप्टी कमिश्नर डा. हिमांशु अग्रवाल ने इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए बताया कि जिला परिषद के लिए कुल 114 नामांकन पत्र दाखिल हुए हैं, जबकि पंचायत समिति रुड़का कलां के लिए 56, पंचायत समिति जालंधर पूर्वी के लिए 64, पंचायत समिति जालंधर पश्चिमी के लिए 66, पंचायत समिति नूरमहल के लिए 68, पंचायत समिति लोहियां खास के लिए 46, पंचायत समिति शाहकोट के लिए 73, पंचायत समिति नकोदर के लिए 79, पंचायत समिति मेहतपुर के लिए 56, पंचायत समिति आदमपुर के लिए 85, पंचायत समिति भोगपुर के लिए 64 तथा पंचायत समिति फिल्लौर के लिए कुल 88 नामांकन दाखिल हुए हैं।

डा. अग्रवाल ने बताया कि नामांकन पत्रों की जांच 5 दिसंबर 2025 को होगी तथा नामांकन 6 दिसंबर 2025 को दोपहर 3 बजे तक वापस लिए जा सकेंगे। उन्होंने आगे बताया कि मतदान 14 दिसंबर 2025 को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक बैलेट पेपर के माध्यम से होगा तथा डाले गए मतों की गिनती 17 दिसंबर 2025 को सुबह 8 बजे से शुरू होगी।

जापान दौरे के तीसरे दिन सीएम ने 500 करोड़ का निवेश सुरक्षित किया

टोयोटा की स्टील कंपनी आइची स्टील कॉर्पोरेशन के साथ समझौता संपन्न

• **जालंधर ब्रीज.** चंडीगढ़

अपने जापान दौरे के तीसरे दिन पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने प्रदेश के लिए 500 करोड़ रुपए का निवेश सुरक्षित किया है, जिसमें जापान की स्टील कंपनी आइची स्टील ने प्रदेश में वर्धमान स्पेशल स्टील्स के साथ अपने सहयोग को बढ़ाने का आश्वासन दिया है। आइची स्टील और वर्धमान स्पेशल स्टील्स ने मुख्यमंत्री की मौजूदगी में समझौते पर हस्ताक्षर किए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह प्रदेश के लिए एक स्वर्णिम दिन है क्योंकि आइची स्टील कॉर्पोरेशन, जिसे टोयोटा की स्टील शाखा के रूप में जाना जाता है, ने प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि आइची स्टील की वर्धमान में पहले से ही लगभग 24.9 प्रतिशत हिस्सेदारी है और यह मुख्य तकनीकी साझेदार के रूप में पंजाब के औद्योगिक परिवेश में एक मजबूत तथा विकसित हो रही भारत-जापान साझेदारी का प्रतीक है।

भगवंत सिंह मान ने कहा कि जापान की अग्रणी स्टील कंपनी पंजाब में भविष्य की फैक्ट्री संचालन का अध्ययन करेगी, जिसमें लगभग 500 करोड़ रुपये के संभावित निवेश के लिए मूल्यांकन शामिल है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में वर्धमान स्पेशल स्टील्स के साथ आइची स्टील की साझेदारी को मजबूत और सुदृढ़ करने के लिए पंजाब सरकार की ओर से पूर्ण सहयोग का भरोसा दिलाया। उन्होंने जोर देकर कहा कि मौजूदा जापानी कंपनियों को प्रदेश में उनके कारोबार और संचालन के विस्तार में सहायता करना पंजाब की प्रमुख प्राथमिकता है।मुख्यमंत्री ने आइची को 13-15 मार्च, 2026 को इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, मोहाली में होने वाले प्रगतिशील पंजाब निवेशक सम्मेलन 2026 में भाग लेने का न्योता भी दिया।

फूड कमीशन के सदस्य चेतन प्रकाश धालीवाल की ओर से जिला होशियारपुर का औचक दौरा

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत चल रही विभिन्न योजनाओं का किया निरीक्षण

• **जालंधर ब्रीज.** होशियारपुर

पंजाब राज्य खाद्य आयोग के सदस्य चेतन प्रकाश धालीवाल ने जिला होशियारपुर का अचानक दौरा किया। इस दौरे के दौरान उन्होंने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत चल रही विभिन्न योजनाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान सरकारी एलिमेंट्री स्कूल अहिराना खुर्द, सरकारी एलिमेंट्री स्कूल पुरहीरां-2, सरकारी एलिमेंट्री स्कूल पुरहीरां-1, आंगनवाड़ी केंद्र कोड नं. 2, 3 और 23 अहिराना खुर्द, आंगनवाड़ी केंद्र कोड नं. 202 पुरहीरां तथा राशन डिपो कायमपुर और ब्लॉक-2 छौनी कलां (कैंप) आदि का दौरा किया गया। उन्होंने बताया कि दौरा की शुरुआत में सरकारी एलिमेंट्री स्कूल अहिराना खुर्द का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान स्कूल में चल रही मिड-डे-मील योजना की जांच की गई। जांच में पाया गया कि स्कूल में सफाई व्यवस्था बहुत खराब थी। बच्चों को दिए जाने वाले पीने के पानी का टी.डी.एस. भी चेक किया गया।

उपरोक्त स्कूलों में पाई गई खामियों के संबंध में मौके पर मौजूद जिला शिक्षा अधिकारी को इन कमियों को दूर करने तथा संबंधित अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई कर आयोग को रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए गए। स्कूलों के निरीक्षण के बाद आंगनवाड़ी केंद्रों का दौरा किया गया। आंगनवाड़ी केंद्र कोड नं. 2 और 3 अहिराना खुर्द में लाभार्थियों तथा उन्हें दिए जा रहे लाभों की जानकारी ली गई। केंद्रों के कार्य से सदस्य ने संतोष व्यक्त किया तथा आगे सुधार के लिए दिशा-निर्देश भी दिए। इसके बाद राशन डिपो कायमपुर और ब्लॉक-2 छावनी कलां (कैंप) में गेहूं वितरण का निरीक्षण किया गया। सदस्य महोदय ने जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक को डिपो पर जागरूकता बैनर लगवाने के निर्देश दिए।

ज़िला परिषद के लिए 64 और ब्लॉक समितियों के लिए 424 नामांकन

कपूरथला (जालंधर ब्रीज). ज़िला परिषद और ब्लॉक समिति के चुनावों के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया पूरी हो गई है। अंतिम दिन, ज़िला परिषद के लिए कुल 64 और ब्लॉक समिति के लिए 424 नामांकन भरे गए। ज़िला मजिस्ट्रेट सह डिप्टी कमिश्नर अमित कुमार पांचाल ने बताया कि नामांकन पत्रों की पड़ताल 05.12.2025 (शुक्रवार) को होगी और 06.12.2025 (शनिवार) शाम 03:00 बजे तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। नामांकनों में ब्लॉक समिति कपूरथला के लिए 110, नडाला के लिए 89, फगवाड़ा के लिए 99, फत्तूढींगा के लिए 56 और सुल्तानपुर लोधी के लिए 70 नामांकन शामिल हैं। ज़िला चुनाव अधिकारी ने बताया कि चुनाव 14.12.2025 (रविवार) को सुबह 08:00 बजे से शाम 04:00 बजे तक मतपत्रों (बैलेट पेपरों) के उपयोग से होंगे। मतदान हुई वोटों की गिनती 17.12.2025 (बुधवार) को इस उद्देश्य के लिए स्थापित किए गए मतगणना केंद्रों पर होगी।

सिरसा में नशा उन्मूलन, पर्यावरण संरक्षण और समाज में मीडिया की भूमिका पर 'वार्ता' का आयोजन

सकारात्मक रिपोर्टिंग एवं सामूहिक प्रयास से समाज में बदलाव संभव: उपायुक्त शांतनु शर्मा

• **जालंधर ब्रीज.** सिरसा

भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रैस इंफोरमेशन ब्यूरो, चंडीगढ़ द्वारा वीरवार को हरियाणा के सिरसा में वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ को समर्पित मीडिया कार्यशाला 'वार्ता' का आयोजन किया गया। कार्यशाला में नशा उन्मूलन, पर्यावरण संरक्षण और समाज में मीडिया की भूमिका आदि विषयों पर चर्चा की गई। इसका उद्देश्य इन विषयों पर विभिन्न आयामों पर सरकार और चौथे स्तंभ के बीच सार्थक संवाद और विचारों के उपयोगी आदान-प्रदान को बढ़ावा देना था। जिला प्रशासन की ओर से इस मीडिया कार्यशाला में उपायुक्त शांतनु शर्मा, पुलिस अधीक्षक सिरसा दीपक सहारण, पुलिस अधीक्षक डबवाली निकिता खट्टर सहित जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। कार्यशाला में उपायुक्त शांतनु शर्मा ने कहा कि मीडिया की सकारात्मक भूमिका एवं किसानों और औद्योगिक संस्थानों के योगदान से अबकी बार पराली जलाने की घटनाओं में पिछले वर्ष के मुकाबले काफी कमी आई है। विभाग और किसानों के बीच में बेहतर सामंजस्य स्थापित हुआ है। प्रशासन द्वारा विभिन्न मुहिम चलाकर पर्यावरण से संबंधित लोगों को जागरूक किया गया। सभी के सामूहिक प्रयासों से जिला में पराली जलाने की घटना में कमी आई है और फसल अवशेष प्रबंधन को लेकर कृषि विभाग द्वारा किसानों को जागरूक किया गया है। उन्होंने कहा कि नशे के प्रति जनता में जागरूकता लाने में मीडिया महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है।

चुनाव पर्यवेक्षक की ओर से जिला परिषद व पंचायत समिति चुनावों की तैयारियों का जायजा

होशियारपुर (जालंधर ब्रीज). पंजाब राज्य चुनाव आयोग की ओर से जिला परिषद व पंचायत समिति के चुनावों के लिए नियुक्त किए गए चुनाव पर्यवेक्षक कंवल प्रीत बराड़ (आई.ए.एस.) ने आज जिला प्रशासकीय परिसर होशियारपुर में सिविल एवं पुलिस अधिकारियों के साथ चुनाव तैयारियों का जायजा लेने के लिए विशेष बैठक की।

बैठक के दौरान डिप्टी कमिश्नर-कम-जिला निर्वाचन अधिकारी आशिका जैन, एस.एस.पी संदीप कुमार मलिक तथा अन्य अधिकारियों से चर्चा के दौरान चुनाव पर्यवेक्षक द्वारा निर्देश दिए गए कि पूरी चुनाव प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी एवं निष्पक्ष ढंग से संपन्न करना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने नामांकन, आचार संहिता लागू करने, सुरक्षा व्यवस्था आदि का जायजा लिया।

इस मौके पर जिला निर्वाचन अधिकारी आशिका जैन ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा निष्पक्ष व पारदर्शी चुनावों के लिए पुख्ता प्रबंध कर लिए गए हैं।

मीत हेयर ने चंडीगढ़ को पूरी तरह पंजाब को सौंपने की मांग की

• **जालंधर ब्रीज.** नई दिल्ली/ चंडीगढ़

आम आदमी पार्टी (आप) के सांसद गुरमीत सिंह मीत हेयर ने आज संसद सत्र के बाद एक सख्त बयान जारी करते हुए चेतावनी दी कि केंद्र सरकार पंजाब के सबसे संवेदनशील मुद्दों, जैसे कि चंडीगढ़ की स्थिति, पंजाब यूनिवर्सिटी का केंद्रीयकरण, यूनिवर्सिटी की सीनेट को खत्म करना और चंडीगढ़ को लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा शासित केंद्र शासित प्रदेश बनाने के प्रस्तावों को उठाकर बार-बार "पंजाबियों के सब्र की परीक्षा" ले रही है।

उन्होंने कहा कि इसके बजाय, केंद्र को लंबे समय से की गई राष्ट्रीय प्रतिबद्धता को पूरा करना चाहिए कि चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी के रूप में बनाया गया था और इसे पूरी तरह पंजाब के हवाले किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पंजाब पूरे देश में एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी अपनी कोई राजधानी नहीं है। यह उस राज्य के साथ बड़ा अन्याय है जिसने भारत के लिए सबसे बड़ी कुर्बानियां दीं और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित किया। इसलिए भारत सरकार को अपना वादा पूरा करना चाहिए। मीत हेयर ने याद दिलाया कि आज भी पंजाब के राज्यपाल चंडीगढ़ के प्रशासक के रूप में सेवा निभाते हैं, और ज्यादातर मुख्य प्रशासनिक अधिकारी पंजाब से हैं।

आईपीएल मिनी- ऑक्शन के लिए 1355 खिलाड़ियों की सूची जारी

स्पोर्ट्स डेस्क. इस बार आईपीएल मिनी-ऑक्शन को लेकर खिलाड़ियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि मौजूद जानकारी के अनुसार 1,355 खिलाड़ियों ने पंजीकरण कराया है। इनमें 1,062 भारतीय और 293 विदेशी खिलाड़ी शामिल हैं। इतनी बड़ी संख्या में आवेदन आने के बावजूद एक नाम "ग्लेन मैक्सवेल" सबसे ज्यादा चर्चा में है। मैक्सवेल ने पहली बार खुद को ऑक्शन प्रक्रिया से दूर रखा है। बता दें कि मैक्सवेल आईपीएल के 13 सीज़न और 141 मैचों में हिस्सा ले चुके हैं और इंस्टाग्राम पर उन्होंने यह घोषणा करते हुए लिखा कि वह लीग द्वारा दिए गए अनुभवों और यादों के लिए आभारी हैं।

गौरतलब है कि इस बार ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका और अफगानिस्तान के कई बड़े अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी भी रजिस्टर में शामिल हैं। कैमरन ग्रीन, जॉश इंग्लिस, स्टीव स्मिथ, डेवन कॉनवे, राखिन

रविंद्रा, जॉनी बैर्स्टो और वानिंदु हसरंगा जैसे नाम 13 पन्नों की इस विस्तृत सूची में जगह बनाए हुए हैं। इंग्लिस की एंट्री ने तो उनके पिछले फ्रेंचाइज़ी को भी चौंका दिया है, क्योंकि उनकी शादी के कारण उपलब्धता अभी स्पष्ट नहीं है।

भारतीय खिलाड़ियों में मयंक अग्रवाल, केएस भरत, राहुल चाहर, रवि बिश्नोई, दीपक हूडा, वेंकटेश अय्यर, पृथ्वी शॉ और उमेश यादव जैसे खिलाड़ी प्रमुख दावेदारों में शामिल हैं। सूची में 212 कैप्ड और 1,121 अनकैप्ड खिलाड़ी हैं। रजिस्टर के अनुसार 45 खिलाड़ियों का बेस प्राइस 2 करोड़ रुपये है, जिनमें भारत से सिर्फ रवि बिश्नोई और वेंकटेश अय्यर शामिल हैं। विदेशी खिलाड़ियों में ग्रीन, स्टीव स्मिथ, मतीशा पथिराना, मुजीब उर रहमान, नॉर्ट्जे और मुस्तफिजुर जैसे नाम 2 करोड़ की कैटेगरी में हैं। ऑक्शन से पहले टीमों के पास खासा बजट भी मौजूद है। नवंबर 15 की रिटेनशन डेडलाइन के बाद 10 फ्रेंचाइज़ियों के पास कुल 237.55 करोड़ रुपये का पर्स उपलब्ध है। इनमें कोलकाता नाइट राइडर्स के पास 64.30 करोड़ रुपये के साथ सबसे बड़ा पर्स है। चेन्नई सुपर किंग्स 43.40 करोड़ रुपये के साथ दूसरे स्थान पर है। बता दें कि इस बार 77 स्लॉट खाली हैं, जिनमें से 31 विदेशी खिलाड़ी भी शामिल किए जा सकते हैं। फ्रेंचाइज़ियों को 5 दिसंबर तक अंतिम सूची की पुष्टि करने का समय दिया गया है।

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) पंजाब, चंडीगढ़ ने किया सालाना कल्चरल प्रोग्राम का सफलतापूर्वक आयोजन

चंडीगढ़ (जालंधर ब्रीज). कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) पंजाब, चंडीगढ़ का वार्षिक सांस्कृतिक कार्यक्रम 4 दिसंबर 2025 को टैगोर थिएटर में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, जो कला और संस्कृति का एक शानदार उत्सव रहा। इस अवसर पर अशीम कुमार घोष, राज्यपाल, हरियाणा एवं उनकी धर्मपत्नी मित्रा घोष मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे।

कार्यक्रम में राज्य एवं संघ शासित प्रदेश चंडीगढ़ के अतिरिक्त केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में सर्वप्रथम प्रधान महालेखाकार नाज़ली जे. शाईन, आई.ए.ए.एस, द्वारा माननीय मुख्य अतिथि व अन्य उपस्थित दर्शकों का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। तत्पश्चात मुख्य अतिथि के द्वारा दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत की गयी। अपने उद्बोधन में माननीय मुख्य अतिथि ने विभाग द्वारा सांस्कृतिक समरसता एवं कर्मचारी सहभागिता को बढ़ावा देने के प्रयासों की सराहना की एवं सभी प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया। इसी क्रम में सरस्वती वंदना के साथ शास्त्रीय नृत्य, पंजाबी गिद्धा और भांगड़ा प्रस्तुतियों, गतिशील हरियाणवी नृत्य एवं अन्यप्रस्तुतियों से मंच जीवंत हो उठा।

Printed, Published & Owner by ATUL SHARMA & Printed at DB Corp Ltd, Near Subhanpur Bus Stand,Hamira, Kapurthala-144802(Punjab) and Published from ATUL SHARMA, NN453 GOPAL NAGAR JALANDHAR (PUNJAB)
Editor : ATUL SHARMA*
*Responsible for selection of News under the PRB ACT. PUNHIN/2019/77863, All Rights Reserved. Reproduction in whole or in Part without permission is prohibited. All disputes shall be settled at Jalandhar jurisdiction only.